गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 239
दि. 30.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

अरावली की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप, खनन पर पुराने आदेश को रोककर नए सिरे से जांच का रास्ता साफ

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली खनन से जुड़े अपने ही पूर्व आदेश पर रोक लगाकर यह साफ कर दिया है कि पर्यावरण जैसे संवेदनशील विषय पर किसी भी तरह की अस्पष्टता या जल्दबाजी स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत का यह कदम न केवल कानूनी दृष्टि से अहम है, बल्कि यह देश में विकास और प्रकृति के बीच संतुलन को लेकर चल रही बहस को भी नई दिशा देता है। अरावली पहाड़ियां सदियों से उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ रही हैं। राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली यह पर्वत श्रृंखला रेगिस्तान के विस्तार को रोकने, भूजल को संरक्षित करने और जैव विविधता को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में जब अरावली की परिभाषा को लेकर यह बात सामने आई कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को इस श्रेणी से बाहर माना जा सकता है, तो पर्यावरणविदों से लेकर आम नागरिकों तक में चिंता की लहर दौड़ गई। आशंका यह थी कि इस व्याख्या के बाद खनन, रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर रास्ता खुल सकता है। इन्हीं आशंकाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने 20 नवंबर के आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस पूरे मामले में कई ऐसे बिंदु हैं, जिन पर स्पष्टीकरण जरूरी है और बिना गहन अध्ययन के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने इस विषय पर एक नई समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि अरावली की भौगोलिक सीमा, उसकी वैज्ञानिक परिभाषा और संरक्षण से जुड़े पहलुओं

पर विस्तार से विचार किया जा सके।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार अदालत के निर्देशों का सम्मान करती है। उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि मंत्रालय नई समिति को हर जरूरी सहयोग देगा। मंत्री ने साफ किया कि फिलहाल अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज देने या पुरानी लीज के नवीनीकरण पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। सरकार का दावा है कि वह अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण के लिए राहत की खबर बताया है। पार्टी का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो अरावली को भारी नुकसान पहुंच सकता था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस आदेश को 'उम्मीद की किरण' बताते हुए कहा कि अब इस मुद्दे पर और गंभीरता से अध्ययन होगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इस नई परिभाषा का विरोध पहले ही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान कर चुके थे।

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की है। पार्टी का आरोप है कि अदालत का ताजा आदेश उन सभी तर्कों को कमजोर करता है, जिनके आधार पर नई परिभाषा को आगे बढ़ाया जा रहा था। कांग्रेस का कहना है कि विकास के नाम पर अरावली को खनन और रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए खोलने की कोशिश की जा रही थी, जो देश के पर्यावरणीय भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती थी।

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में 24 दिसंबर को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश भी चर्चा में हैं। इन निर्देशों में कहा गया था कि नए खनन की मंजूरी पर रोक संपूर्ण अरावली क्षेत्र पर लागू रहेगी। सरकार का तर्क है कि इन निर्देशों का उद्देश्य अरावली को एक सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में संरक्षित करना और अनियमित खनन गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अरावली की अखंडता बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।

इसके साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी आईसीएफआरई को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईसीएफआरई को पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करने को कहा गया है, जहां खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यह अध्ययन पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों के अतिरिक्त होगा और इसके आधार पर भविष्य की नीति तय की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह अध्ययन निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से किया गया, तो अरावली संरक्षण को लेकर एक ठोस रोडमैप तैयार हो सकता है। अरावली का सवाल केवल कानूनी या राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों से भी गहराई से जुड़ा है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बढ़ता प्रदूषण और घटता भूजल स्तर पहले ही देश के कई हिस्सों में गंभीर संकट पैदा कर चुके हैं। अरावली का क्षरण इन समस्याओं को और गहरा कर सकता है, खासकर दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में, जहां प्रदूषण और जल संकट पहले से ही विकराल रूप ले चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस मायने में भी अहम है कि यह विकास की अवधारणा पर पुनर्विचार की जरूरत को रेखांकित करता है। विकास वह नहीं जो प्रकृति को नष्ट करके हासिल किया जाए, बल्कि वह है जिसमें आने वाली पीढ़ियों के हित सुरक्षित रहें। अरावली जैसी प्राचीन पर्वत श्रृंखला को बचाना केवल पर्यावरण संरक्षण का सवाल नहीं, बल्कि यह देश की दीर्घकालिक स्थिरता और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।

अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि नई समिति की रिपोर्ट क्या दिशा दिखाती है और सरकार उस पर किस तरह अमल करती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक जरूरी विराम देकर यह अवसर दिया है कि अरावली के भविष्य पर सोच-समझकर, वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से निर्णय लिया जाए। उम्मीद यही है कि यह विराम केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित न रहे, बल्कि अरावली को बचाने की दिशा में एक ठोस और ईमानदार प्रयास की शुरुआत बने।

पार्टी अधिवेशन से पहले उत्तर कोरिया का शक्ति प्रदर्शन, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के परीक्षण से अमेरिका-दक्षिण कोरिया की बढ़ी चिंता

(जीएनएस)। सियोल। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरियाई मीडिया के अनुसार यह परीक्षण रविवार को देश के पश्चिमी तट से किया गया और सोमवार को इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब अगले वर्ष की शुरुआत में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी का महत्वपूर्ण अधिवेशन होने वाला है। पांच साल में एक बार होने वाले इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी मंच से उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ अपने भविष्य के संबंधों को लेकर नई प्राथमिकताएं स्पष्ट कर सकते हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, किम जोंग उन ने स्वयं इन परीक्षणों की निगरानी की और परिणामों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और बाहरी सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह परीक्षण आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग है। किम ने यह भी कहा कि इस तरह के हथियार परीक्षणों

का उद्देश्य युद्ध की स्थिति से निपटने की देश की वास्तविक क्षमता को परखना है। उत्तर कोरिया लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह किसी भी दबाव या प्रतिबंध के बावजूद अपनी सैन्य तैयारियों से पीछे हटने वाला नहीं है।

दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार सुबह उत्तर कोरिया की राजधानी क्षेत्र के आसपास से कई क्रूज मिसाइलें दागी गईं। दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा कि वह इन प्रक्षेपणों पर करीबी नजर बनाए हुए थी और अमेरिका के साथ अपने मजबूत सैन्य गठबंधन के तहत किसी भी संभावित उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सियोल ने साफ किया कि क्षेत्रीय सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और उत्तर कोरिया की हर गतिविधि पर सतर्क निगरानी रखी जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह परीक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि, क्रूज मिसाइलों के परीक्षण पर सीधे तौर पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये मिसाइलें अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं हैं। क्रूज मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं और आधुनिक रडार प्रणालियों की पकड़ से बच निकलने में सक्षम होती हैं, जिससे इन्हें रोकना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

विश्लेषकों का मानना है कि वर्कर्स पार्टी के अधिवेशन से पहले इस तरह का मिसाइल परीक्षण उत्तर कोरिया की रणनीतिक सोच को दर्शाता है। किम जोंग उन अक्सर बड़े राजनीतिक आयोजनों से पहले सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर देश के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ बाहरी दुनिया को भी स्पष्ट संदेश देते रहे हैं। यह परीक्षण भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए उत्तर कोरिया यह जताना चाहता है कि वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और अपनी सुरक्षा नीति पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगा।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया पहले ही उत्तर कोरिया के हालिया कदमों को लेकर चिंता जता चुके हैं। दोनों देश मानते हैं कि इस तरह के परीक्षण कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को और बढ़ा सकते हैं। इसके बावजूद उत्तर कोरिया लगातार यह दावा करता रहा है कि उसके हथियार कार्यक्रम पूरी तरह रक्षात्मक हैं और किसी देश के खिलाफ आक्रामक इरादे नहीं रखते। किम जोंग उन के बयान भी इसी लाइन में आते हैं, जिनमें वे बाहरी खतरों के जवाब में आत्मरक्षा की बात करते हैं।

पूर्व सैनिकों के साथ रोजगार और इलाज में भेदभाव का सवाल, तय कोटे के बावजूद भर्ती नगण्य, संसद की समिति में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर संसद की स्थायी समिति की बैठक में ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच गहरे अंतर को उजागर कर दिया। बैठक में बताया गया कि नियमों के मुताबिक सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए 10 से 25 प्रतिशत तक का आरक्षण निर्धारित है, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2019 में कुल भर्ती में उनका हिस्सा महज 1.9 प्रतिशत ही रहा। यह आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि उन लाखों पूर्व सैनिकों के भविष्य पर भी सवाल खड़ा करता है, जिन्होंने अपने जीवन का अहम हिस्सा देश की सेवा में समर्पित किया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हर साल करीब 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन उनके पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था बेहद कमजोर है। तय कोटा होने के बावजूद नौकरियों में उनकी भागीदारी इतनी कम होना यह दर्शाता है कि या तो नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित हैं या फिर उन्हें लागू करने की इच्छाशक्ति की कमी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

बैठक में पूर्व सैनिकों के इलाज से जुड़ी समस्याओं पर भी गंभीर चिंता जताई गई। राहुल गांधी ने कहा कि जब पूर्व सैनिकों को ईसीएचएस या अन्य योजनाओं के तहत रेफरल प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जाता है, तो उन्हें वहां अक्सर अपमान और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई निजी अस्पताल यह कहकर इलाज से मना कर देते हैं कि सरकार की ओर से उनका पिछला भुगतान लंबित है। ऐसे में पूर्व सैनिक और उनके परिवार इलाज के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक और अमानवीय स्थिति बताया। स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि कैंसर, किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पूर्व सैनिकों को सिर्फ 75 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा समय में इतनी कम राशि में इन बीमारियों का इलाज संभव ही नहीं है। उन्होंने सरकार से इस सीमा को यथार्थवादी स्तर तक बढ़ाने की मांग की, ताकि पूर्व सैनिकों को बेहतर और समय पर इलाज मिल सके। उनका कहना था कि देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को इलाज के समय आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, यह पूरे सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। बैठक में कुछ अन्य सांसदों ने भी पूर्व सैनिकों के पुनर्वास को लेकर अपने विचार रखे। सुझाव दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में पूर्व सैनिकों की भर्ती को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाए और इसके लिए स्पष्ट लक्ष्य तय किए जाएं। कई सांसदों ने कहा कि पूर्व सैनिक अनुशासन, नेतृत्व और तकनीकी कौशल से लैस होते हैं, ऐसे में वे पीएसयू और सरकारी संस्थानों के लिए एक बड़ी संपत्ति साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद अगर उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो यह नीति निर्धारण और प्रशासनिक इच्छाशक्ति दोनों पर सवाल खड़े करता है। बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन सिंह ने की। इसमें कांग्रेस के राहुल गांधी के अलावा बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल, समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह समेत कई दलों के सांसद शामिल हुए। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक में पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर और विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, समिति के कई सदस्यों ने माना कि रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर पूर्व सैनिकों की स्थिति में सुधार की तत्काल जरूरत है।

अब हर तौल और हर मीटर पर होगी सख्त नजर, गलत माप से उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में केंद्र का बड़ा फैसला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बाजार से खरीदी जाने वाली सब्जी का वजन हो, घर में आने वाला बिजली और पानी का बिल हो या फिर अस्पताल में की जाने वाली जांच—इन सभी में माप-तौल की गड़बड़ियों से आम लोगों को अब काफी हद तक राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए माप-तौल से जुड़े उपकरणों की जांच व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने देश की 11 निजी संस्थाओं को सरकार द्वारा मान्यता देते हुए 12 परीक्षण केंद्रों को मंजूरी दी है। इस फैसले से माप-तौल और विभिन्न मीटरों की जांच का दायरा व्यापक होगा और सत्यापन प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी, जिसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।

अब तक माप-तौल से जुड़े उपकरणों की जांच और सत्यापन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकारी विभागों के पास थी। कई राज्यों में कर्मचारियों और संसाधनों की कमी के कारण यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाती थी। दुकानों, कारखानों, मंडियों, पेट्रोल पंपों और सेवा प्रदाताओं के यहां इस्तेमाल होने वाले तराजू, मीटर और अन्य उपकरण लंबे समय तक बिना जांच के चलते रहते थे। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता था, जिन्हें कम तौल, गलत बिल और गलत माप जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई में देरी होती थी, जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा व्यवस्था पर कमजोर पड़ता था।

निजी परीक्षण केंद्रों को मान्यता मिलने से इस स्थिति में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। अब देश के अलग-अलग हिस्सों में ज्यादा संख्या में जांच केंद्र उपलब्ध होंगे, जिससे उपकरणों का सत्यापन समय पर हो सकेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बाजार में इस्तेमाल हो रहे माप-तौल उपकरण मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। नई व्यवस्था के तहत 18 तरह के उपकरणों को जांच के दायरे में शामिल किया गया है, जो आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें पारंपरिक तराजू और बाट के साथ-साथ बिजली मीटर, पानी का मीटर, गैस मीटर, प्रवाह मापक, सांस जांचने की मशीन, गति मापक, रक्तचाप मापने की मशीन और तापमापी जैसे उपकरण भी शामिल हैं।

इस कदम का सबसे बड़ा असर बिजली और पानी के बिलों पर देखने को मिलेगा। लंबे समय से यह शिकायत रहती रही है कि मीटर की गड़बड़ी के कारण उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल चुकाना पड़ता है। अब मीटरों की नियमित और सख्त जांच से यह सुनिश्चित होगा कि बिल वास्तविक खपत के आधार पर ही बने। इसी तरह अस्पतालों और जांच केंद्रों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की सटीकता बढ़ने से मरीजों को सही रिपोर्ट मिलेगी और इलाज पर भरोसा मजबूत होगा। गलत माप या गलत रिपोर्ट के कारण होने वाली परेशानियों और जोखिमों में भी कमी आएगी।

रोजमर्रा के लेन-देन में पारदर्शिता लाने की दिशा में यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। किराना दुकानों, सब्जी मंडियों और थोक बाजारों में तराजू और बाट की नियमित जांच से कम तौलने की शिकायतों पर अंकुश लगेगा। पेट्रोल पंपों पर ईंधन की सही मात्रा मिलने को लेकर उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान से बचाव होगा, बल्कि ईमानदार व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। जो व्यापारी नियमों का पालन करते हैं, उन्हें भी इससे राहत मिलेगी क्योंकि गलत माप-तौल करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई हो सकेगी।

भिवाड़ी में अवैध दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश, गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई में 30 लाख की अल्प्राजोलाम जब्त

अहमदाबाद/भिवाड़ी। देश में नशे के अवैध **(जीएनएस)**। कारोबार पर शिकंजा कसते हुए गुजरात एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही एक अवैध दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में बिना किसी वैध लाइसेंस के अल्प्राजोलाम जैसी प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक दवा का निर्माण किया जा रहा था, जिसे अवैध ड्रग मार्केट में खपाने की तैयारी थी। रविवार को की गई इस छापेमारी में एजेंसियों ने मौके से करीब 22 किलोग्राम साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और तैयार अल्प्राजोलाम बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी जा रही है। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार, गुजरात एटीएस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में फार्मा यूनिट की आड़ में अवैध रूप से नशीली दवाओं का निर्माण किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई और रविवार को संबंधित फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम को बड़ी मात्रा में तैयार अल्प्राजोलाम टैबलेट के साथ-साथ कच्चा माल, केमिकल्स और दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण मिले। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि फैक्ट्री में किसी भी तरह की वैध अनुमति नहीं थी और यहां तैयार की जा रही दवाओं का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाना था।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 5 किलोग्राम तैयार अल्प्राजोलाम और 17 किलोग्राम अन्य साइकोट्रोपिक पदार्थ बरामद किए, जो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे। कुल मिलाकर 22 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में अल्प्राजोलाम का अवैध निर्माण न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने की एक सुनियोजित साजिश भी है। बरामद दवाओं को सील कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि इनके स्रोत और नेटवर्क की पूरी जानकारी सामने आ सके।

इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अंशुल शास्त्री, अखिलेश मौर्य और कृष्ण कुमार यादव के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड अंशुल शास्त्री है, जो अपनी एक ट्रेडिंग फर्म के जरिए फार्मास्यूटिकल कच्चा माल खरीदता था। इसी कच्चे माल का इस्तेमाल अवैध रूप से अल्प्राजोलाम बनाने में किया जाता था। अंशुल ने अखिलेश मौर्य के साथ मिलकर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फार्मा यूनिट किराए पर ली थी, ताकि अवैध गतिविधियों को वैध उद्योग का रूप दिया जा सके। उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में केमिस्ट कृष्ण कुमार यादव की अहम भूमिका सामने आई है, जो दवा बनाने की तकनीकी जानकारी रखता था और निर्माण कार्य को अंजाम देता था।

एजेंसियों का कहना है कि यह गिरोह काफी समय से सक्रिय था और अलग-अलग राज्यों में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के संपर्क में था। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी संकेत मिले हैं कि तैयार की गई अल्प्राजोलाम को राजस्थान, गुजरात और आसपास के राज्यों में सप्लाई करने की योजना थी।

संपादकीय

दोस्ती अखबार से

ऐसे समय में जब तकनीक ने जीवन को अभूतपूर्व गति दे दी है और मोबाइल स्क्रीन बच्चों की आंखों के सामने दुनिया का सबसे बड़ा सच बनती जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार का स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य करने का निर्णय वास्तव में उम्मीद की एक उजली किरण की तरह सामने आता है। यह फैसला केवल एक शैक्षणिक गतिविधि भर नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को सोचने, समझने और तर्क करने की दिशा में लौटाने का एक सार्थक प्रयास है। आज जब बच्चे डिजिटल मीडिया पर दिखने वाली हर सूचना को बिना सवाल किए अंतिम सत्य मानने लगे हैं, तब सुबह की प्रार्थना सभा में दस मिनट अखबार पढ़ने की अनिवार्यता उन्हें ठहरकर पढ़ने, समझने और विचार करने का अवसर देगी। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव बहुत गहरे और स्थायी हो सकते हैं।

सरकार द्वारा यह भी तय किया गया है कि प्रतिदिन पांच कठिन शब्द उनके अर्थ के साथ ब्लैकबोर्ड पर लिखे जाएंगे। यह पहल भाषा के प्रति बच्चों की समझ को गहरा करेगी। शब्द केवल भाषा की इकाई नहीं होते, वे विचारों के वाहक होते हैं। जब शब्द समृद्ध होते हैं, तो सोच भी समृद्ध होती है। अखबार पढ़ने से बच्चों का शब्द भंडार बढ़ेगा, वाक्य संरचना सुधरेगी और वे अपनी बात बेहतर तरीके से कहने में सक्षम होंगे। आज यह एक स्थापित सच्चाई है कि छात्रों के सबसे कम अंक अक्सर मातृभाषा में आते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि बच्चे पढ़ने से दूर होते जा रहे हैं। अखबार जैसी सामग्री, जो सरल भी है और समसामयिक भी, भाषा से दूरी को कम कर सकती है। यह भी निर्विवाद है कि अखबार पढ़ने से सामान्य ज्ञान अपने आप बढ़ता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी बच्चों को दुनिया से जोड़ती है। वे केवल अपने घर, मोहल्ले या स्कूल तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सोचने लगते हैं। संपादकीय पढ़ना उन्हें विचारों की गहराई से परिचित कराता है। वहां केवल खबर नहीं होती, बल्कि खबर का विश्लेषण, उसके सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक आयाम होते हैं। इससे बच्चों में आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बच्चों की उंगलियां किताबों के पन्ने पलटने के बजाय मोबाइल के की-बोर्ड पर थिरकती रहती हैं। स्क्रीन टाइम बच्चों के जीवन में इस कदर हावी हो गया है कि वास्तविक दुनिया उनके लिए आभासी दुनिया से कम आकर्षक लगने लगी है। विभिन्न सर्वे यह संकेत दे चुके हैं कि भारत में पांच साल तक के बच्चे भी रोजाना दो घंटे से अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि दो साल जैसे कम उम्र के बच्चे भी औसतन 1.2 घंटे स्क्रीन के सामने रहते हैं। एक चौथाई बच्चों की इंटरनेट तक सीधी पहुंच है। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि एक गहरी सामाजिक चिंता की ओर इशारा करते हैं। ऐसे समय में जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर रोक लगाने जैसे कड़े फैसले ले रहे हैं, भारत में दस साल से कम उम्र के बच्चों के भी सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय हैं। यह स्थिति केवल तकनीक के दुरुपयोग की नहीं, बल्कि बचपन के धीरे-धीरे छिन जाने की कहानी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों की मासूमियत को निगल रहे हैं, उन्हें समय से पहले वयस्क बना रहे हैं और कई बार मानसिक तनाव, तुलना की भावना और अवसाद की ओर भी धकेल रहे हैं। इस संदर्भ में अखबार पढ़ने की आदत बच्चों को एक संतुलित, शांत और भरोसेमंद सूचना माध्यम से जोड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय कि मॉर्निंग असेंबली के दौरान बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के समाचार पत्र पढ़ने को दिए जाएंगे, बेहद व्यावहारिक और दूरदर्शी है। यह पहल सभी सरकारी बेसिक और सेकेंडरी स्कूलों के लिए अनिवार्य की गई है, लेकिन निजी स्कूल भी चाहें तो इसे अपना सकते हैं। वास्तव में, यदि निजी स्कूल भी इस पहल से जुड़ते हैं, तो इसका प्रभाव और व्यापक हो सकता है। बच्चों को पाठ्यक्रम से इतर पढ़ने की आदत डालना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा ने पढ़ने को केवल नंबर लाने का साधन बना दिया है, जबकि पढ़ना व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। अखबार आज भी भरोसेमंद सूचना का माध्यम हैं, यह बात अनेक सर्वे और शोधों में सामने आ चुकी है। अखबारों में प्रकाशित होने वाली खबरें कई स्तरों की जांच और संपादकीय प्रक्रिया से गुजरती हैं। संपादक नामक संस्था खबरों की विश्वसनीयता की गारंटी होती है। इसके विपरीत सोशल मीडिया पर सूचनाओं का अंबार है, लेकिन वहां जिम्मेदारी का अभाव है। कोई भी व्यक्ति बिना तथ्य जांचे कुछ भी पोस्ट कर सकता है। निहित स्वार्थी तत्व भ्रामक और उकसाऊ सूचनाएं फैलाते रहते हैं, जिनका प्रभाव बच्चों और किशोरों के मन पर बहुत गहरा पड़ता है। ऐसे में अखबार पढ़ना बच्चों को तथ्य और अफवाह के अंतर को समझने की क्षमता देता है।

प्रधानमंत्री के चर्च जाने का निहितार्थ

"लोकतंत्र की मजबूती के लिए एकता एक अनिवार्य शर्त है जो भारत में सर्वधर्म समभाव की अवधारणा में निहित है। प्रधानमंत्री का दिल्ली में ऐतिहासिक चर्च में जाना भी इसी ओर संकेत करता है। इसके अलावा किसी भी समुदाय की धार्मिक आस्था में दखलअंदाजी नहीं करना एकजुटता कायम रखने के लिए आवश्यक है। यह सोच 'आइडिया ऑफ इंडिया' के अनुकूल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के अवसर पर चर्च गए, 1931 ईस्वी का यह शानदार 'कैथेड्रल चर्च ऑफ़ द रिडेम्पशन' संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के ऐन पास है– इसकी नलीदार मेहराबें और नज़ाकत भरा गुंबद 'जिन्होंने लॉर्ड इरविन का भी दिल जीत लिया था', और इसका पुराना ऑर्गन अभी भी सही सलामत है। यह सिर्फ़ दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में चर्च गए हों, पहली बार, दो साल पहले, दिल्ली के बीचोंबीच गोल मार्केट स्थित सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में गए थे। परम आदरणीय मुख्य पादरी पॉल स्वरूप द्वारा प्रभु यीशु मसीह से की गई प्रार्थना, जिसे सुनकर कोई भाव-विभोर हो जाए : 'हे पिता, हम जानते हैं कि जिन्हें आप बुलाते हैं, आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और हम जानते हैं प्रभु कि आपने उन्हें हमारे महान राष्ट्र का नेतृत्व करने के इस महत्वपूर्ण काम के लिए चुना है। अतः, हे पिता, मैं आपके विवेक, आपकी सूझबूझ की दोगुनी रहमत के लिए प्रार्थना करता हूं, कि वे इस राष्ट्र को सच्चाई, न्याय व धर्म के रास्ते पर ले जा सकें...।'

आइए एक पल के लिए समझते हैं कि बिशप किस संदर्भ में यह कह रहे होंगे। साल की शुरुआत यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम द्वारा जारी एक बयान से हुई थी, जिसमें कहा गया था कि उसने 2024 में भारत में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और धमकाने की 834 घटनाओं को दर्ज किया है, जोकि 2014 में हुई 127 घटनाओं से कहीं ज़्यादा है। जब प्रेस ने बिशप से पूछा कि क्या वह इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे, तो बिशप ने कहा कि यह सही समय नहीं है। निश्चित रूप से, भारत के ईसाई उम्मीद कर रहे होंगे कि चर्च में प्रधानमंत्री की मौजूदगी से यह संदेश जाएगा कि निर्दोष लोगों के खिलाफ हिंसा रोकने का समय आ गया है।

दिल्ली से, प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचे, 'प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन करने के लिए, जो कई मूर्तियों वाला बगीचा है, जिनमें से एक मूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी की भी है। साल 2014 में उनके जन्मदिन पर, मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि 25 दिसंबर को अब से 'सुशासन दिवस' पुकारा जाएगा, और क्रिसमस अब राष्ट्रीय छुट्टी नहीं होगी। मोदी के चर्च में जाने से, उम्मीद है कि इसका मतलब है कि दोनों संभव हैं। यानी अब आप क्रिसमस और सुशासन, दोनों मना सकते हैं। गत सप्ताह, हरियाणा के हिसार में 160 साल पुराने चर्च के सामने विश्व हिंदू परिषद ने 25 दिसम्बर को 'तुलसी पूजन दिवस' के रूप में मनाया, और प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने को कि कहीं कोई गड़बड़ न हो, लगभग 300 पुलिसकर्मी तैनात किए। रोचक यह कि विश्व हिंदू परिषद के 'हवन' में एक व्यक्ति ने जो जैकेट पहनी थी, उस पर इटैलियन डिज़ाइनर बालेनशियागा का ब्रांड नाम लिखा था, लेकिन शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दक्षिणपंथी निशाना उन अंग्रेज़ों पर साधते हैं जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया था, न कि इटैलियनों पर। हिसार में यह विडंबना नज़रअंदाज़ हो गई तो कोई बात नहीं। यहां रोचक यह है कि हिसार का यह सेंट थॉमस चर्च दिल्ली के उस कैथेड्रल से कहीं ज़्यादा पुराना है, जहां क्रिसमस के दिन प्रधानमंत्री गए थे— 1864 में बना यह गिरजाघर यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक के नाम पर स्थापित किया गया था, जो 52वीं ईस्वी में किश्ती में सवार होकर केरल में धर्म प्रचार करने आए थे। तब फिर, 1800 साल बाद सेंट थॉमस की याद में इतनी दूर हिसार को क्यों चुना गया? यह साफ़ नहीं है, सिवाय इसके कि 1864 तक, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश राज ने सैन्य विद्रोह पर पार पा लिया था, उत्तरी भारत पर उनकी पकड़ कहीं ज्यादा मज़बूत हो गई थी, और छोटे से ईसाई समुदाय को एक चर्च की ज़रूरत थी।

तथ्य है कि हिसार सदियों से भारत में अपनी किस्मत आजमाने वालों के लिए एक पड़ाव के रूप में महत्वपूर्ण स्थान बन चुका था। बाबर ने 1526 में पानीपत की निर्णायक लड़ाई लड़ने जाते वक्त, रास्ते में पड़ने वाले हिसार के शासक हामिद खान को हराने के बाद इसको अपने बेटे हुमायूं को इनाम में दिया था। इब्राहिम लोदी के रास्ते से हटने के बाद, बाबर अब हिंदुस्तान का नया सम्राट बन गया था। साल का यह आखिरी हफ़्ता इतिहास से सीखने का अच्छा समय है। मुसलमानों ने मुसलमानों से लड़ाई लड़ी, जबकि पराए धार्मिक विश्वास वाले इन लोगों की सेनाओं में हिंदू बतौर मुख्य सेनापति दोनों ओर से लड़े। सत्ता जितनी बंदूक के बूते और शासक के करीबी होने पर मिलती है, उतनी आपकी धार्मिक रीतियों के पालन से नहीं। इतिहास से सीधे गत सप्ताह के 'नाम में क्या रखा है' वाली बहस पर आते हैं, जो सिख धर्म के सर्वोच्च धार्मिक स्थल, अकाल तख्त और केंद्र सरकार के बीच 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' का नाम देने को लेकर चल रहे तनाव में सामने आई है - गुरु गोबिंद सिंह के दो सबसे छोटे बेटों को सन् 1704 में इसी दिन सरहिंद में क्रूर औरंगज़ेब के क्रूरतम सूबेदार वज़ीर खान ने ज़िंदा दीवारों में चिनवा दिया था। अकाल तख्त का मानना है कि इस दिन का नामकरण 'साहिबज़ादे शहादत दिवस' किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चों की शहादत उन्हें कालजयी नायक बनाती है—वे कोई साधारण 'बाल', बच्चे या छोटे लड़के नहीं। सिख सांसदों से कहा गया है कि यह मामला केंद्र के साथ उठाएं, और इस बारे में सिख धर्मगुरुओं की एक बैठक बुलाई गई है। अब चूंकि पहली बार प्रधानमंत्री ने ही 9 जनवरी, 2022 को उनके शहीदी दिवस को 'वीर बाल दिवस' मनाने का आह्वान किया था, वह दिन गुरु गोबिंद सिंह का 'प्रकाश पर्व' या जयंती दिवस था –केंद्र सरकार द्वारा 21 नवंबर, 2021 को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के सिर्फ़ छह हफ़्ते बाद। 'कभी हार न मानने वाला' यह दस्तूर आज भी जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी मामले में विफलता और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश पर ज़्यादा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश के हफ़्तों बाद - ये दोनों बीजेपी द्वारा थोपे गए निर्णय थे, और इनको कुछ ही दिनों में वापस लेना पड़ा - इन सबसे बेपरवाह दल पंजाबी वोटरों को लुभाने में लगा हुआ है।

प्रधानमंत्री के 'बाल दिवस' का संस्थागतकरण इसका एक उदाहरण है; हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बार-बार पंजाब जाना और पगड़ी पहनकर पंजाबी मुद्दों पर बोलना दूसरा उदाहरण है। साफ़ है संकेत देने की कोशिशें हो रही हैं, जिसका मकसद 14 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव हैं।

निश्चित रूप से, आने वाला साल लंबा, कठिन और ख़बरों से भरा होगा, क्योंकि 'भारत के विचार' के लिए लड़ाई तेज़ी से जारी है। यह भी निश्चित है कि यह लड़ाई सिर्फ़ राजनीति और राजनीतिक पार्टियों तक सीमित नहीं है, जो अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करने में लगी हैं। एआई के युग में, आपके घरों में पश्चिमीकरण विरोधी बहस क्या रूप धर रही है - क्या यह अभी भी प्रासंगिक है? इससे भी ज़रूरी बिंदु है- क्या कोई सुन रहा है? शायद इसीलिए मातृ-पितृ पूजन दिवस, जो वैलेंटाइन-डे का देसी विकल्प बनने की कोशिश था, बुरी तरह फेल हो गया। सभी को नए साल की शुभकामनाएं!

प्रेरणा

कोहबर की मुस्कान और मर्यादा का विनोद

विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, दो परिवारों और दो संवेदनाओं का मिलन होता है। भारतीय परंपरा में विवाह के बाद के क्षण केवल रस्मों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनमें लोकहास्य, स्नेह, आत्मीयता और शालीन विनोद भी घुला होता है। मिथिला की परंपराओं में यह रंग और गहरा दिखाई देता है, जहां हास्य भी मर्यादा की सीमा में रहकर आत्मा को स्पर्श करता है। राम-सीता विवाह के पश्चात का कोहबर प्रसंग इसी गरिमामय हास्य का एक सुंदर उदाहरण है, जिसमें हंसी है, चुटकी है, पर कहीं भी मर्यादा भंग नहीं होती।

विवाह संपन्न होने के बाद चारों भाइयों को मिथिला की कन्याएं अलग-अलग कक्षों में ले जाती हैं। यह क्षण नवविवाहित जीवन की पहली दहलीज है, जहां संकोच, उत्सुकता और आनंद एक साथ उपस्थित रहते हैं। लक्ष्मण के कक्ष में सखियां अपने स्वभाव के अनुरूप हंसी-मजाक करने लगती हैं। वे छेड़ती हैं, पर वह छेड़छाड़ स्नेह से भरी हुई है, जिसमें कोई कटुता नहीं, केवल अपनापन है। लक्ष्मण स्वभाव से तेजस्वी हैं, पर हृदय से अत्यंत कोमल भी। सखियों की बातों को वे सुनते हैं, मुस्कराते हैं, किंतु उसी क्षण उनके मन में एक विचार कौंध जाता है।

लक्ष्मण को स्मरण आता है कि उनके भैया राम स्वभाव से अत्यंत सरल और गंभीर हैं। वे किसी भी प्रकार के हास्य या छेड़छाड़ का उत्तर तीखे शब्दों में नहीं देते। लक्ष्मण यह सोचकर चिंतित हो उठते हैं कि कहीं सीता की सखियां राम को भी इसी प्रकार छेड़ रही हों और राम अपने स्वभाव के कारण कुछ कह न पा रहे हों। यह चिंता केवल एक भाई की चिंता नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के सम्मान की रक्षा का भाव है। इसी उद्देश्य से लक्ष्मण अपने कक्ष को छोड़कर उस कोहबर की ओर बढ़ते हैं, जहां राम और सीता विराजमान हैं। जैसे ही लक्ष्मण कक्ष में प्रवेश करते हैं, वातावरण में एक क्षण के लिए ठहराव आता है, फिर सीता की सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। उनके लिए यह एक नया अवसर है, एक नया रंग। वे हंसी-हंसी में कह उठती हैं कि अब तो दो दूल्हों को छेड़ने का आनंद मिलेगा। यह कथन सुनने में हल्का है, पर उसके भीतर मिथिला की सहजता और अपनापन छिपा है। सखियां किसी प्रकार का अपमान नहीं कर रहीं, बल्कि इस नवविवाहित वातावरण को और जीवंत बना रही हैं।

सखियां फिर राम और सीता की सुंदरता की तुलना करने लगती हैं। वे कहती हैं कि उनकी सखी सीता राम से अधिक सुंदर हैं और राम तो उनकी मात्र छाया हैं। यह कथन सुनते ही लक्ष्मण के भीतर का भाई जाग उठता है। उन्हें यह स्वीकार नहीं होता कि उनके आराध्य, उनके आदर्श भैया को छाया कहा जाए। वे तुरंत प्रतिवाद करते हैं और कहते हैं कि उनके भैया राम अधिक सुंदर हैं और सीता उनकी छाया हैं। यह संवाद कोई कटु वाद-विवाद नहीं, बल्कि सौंदर्य और प्रेम से भरी हुई एक विनोदी तकरार है। बहस बढ़ती है, पर उसका स्वर अब भी मधुर है। सखियां मुस्कराते हुए कहती हैं कि निर्णय करना बहुत सरल है। वे प्रश्न पूछती हैं कि बताइए, छाया का रंग कैसा होता है। लक्ष्मण बिना किसी हिचक के उत्तर देते हैं—काला। उनका उत्तर तर्कपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः छाया को गहरे रंग से जोड़ा जाता है। पर यही उत्तर सखियों के लिए विजय का द्वार खोल देता है। वे मुस्कराकर कहती हैं कि उनकी सीता तो गोरी हैं और राम श्याम वर्ण के। इससे सिद्ध हुआ कि राम, सीता की छाया हैं।

यह सुनते ही लक्ष्मण निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास इस तर्क का कोई तत्काल उत्तर नहीं होता। वे चुप हो जाते हैं और सखियों की विजयपूर्ण मुस्कान वातावरण में फैल जाती है। यह क्षण केवल हास्य का नहीं, बल्कि विनम्रता का भी है। लक्ष्मण जैसे तेजस्वी और बुद्धिमान व्यक्तित्व का मौन स्वीकार करना यह दर्शाता है कि वे भी मर्यादा और हास्य की गरिमा को समझते हैं। इस पूरे प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हास्य कहीं भी मर्यादा की सीमा को नहीं लांघता। सखियां छेड़ती हैं, पर उनके शब्दों में आदर है। लक्ष्मण प्रतिवाद करते हैं, पर उनमें क्रोध नहीं है। राम और सीता इस पूरे संवाद में मौन रहकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राम का श्याम वर्ण और सीता की गौर वर्ण की तुलना कोई उपहास नहीं, बल्कि सौंदर्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यहां रंग भेद नहीं, बल्कि प्रेम का रंग है।

यह प्रसंग यह भी सिखाता है कि हास्य तब सबसे सुंदर होता है, जब वह अहंकार को तोड़े, रिश्तों को मधुर बनाए और वातावरण को हल्का करे। आज के समय में जहां हास्य अक्सर कटाक्ष और अपमान का रूप ले लेता है, वहां कोहबर का यह प्रसंग हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा हास्य वही है, जो गरिमा के साथ आए। मिथिला की सखियों का विनोद और लक्ष्मण की सरल हार यह दिखाती है कि प्रेम और सम्मान के बीच किया गया हास्य कभी भी कड़वा नहीं होता।

अंततः यह कहा जा सकता है कि राम-सीता विवाह के बाद का यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का प्रतिबिंब है। इसमें भाई का स्नेह है, सखियों की चपलता है, नवविवाहित जीवन की मधुरता है और हास्य की गरिमा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हंसी आवश्यक है, पर वह हंसी मर्यादा के आंचल में सजी हो, तभी वह वास्तव में सुंदर और शाश्वत बनती है।

नया कोल्ड वार क्या है? किनके बीच चल रहा है? इसमें भारत किस भूमिका में है?

द्वितीय विश्व युद्ध की विजय के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच छिड़े शीत युद्ध और इसके वार-पलटवार जैसे युद्धगत प्रभावों से हमलोग वाकिफ हैं। इस दौरान यूएसए और यूएसएसआर की खेमेबाजी भी जगजाहिर रही, जिससे दुनिया के कमजोर देशों के कुछ कुछ हित भी सधे। हालांकि 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखराव के बाद यह खत्म हो गया। लेकिन अमेरिका की बढ़ती वैश्विक चौधराहट के बाद 2010 के दशक में अमेरिका-चीन के बीच फिर से एक 'नया शीत युद्ध' शुरू हो गया, जो अब तलक जारी है। चूंकि यूएसएसआर के पतन में अमेरिकी भूमिका रही, इसलिए उसके अवशेष पर खड़े हुए रूस ने चीन को शह देकर अमेरिका से अपना पुराना हिसाब-किताब चुकता कर लिया। इस प्रकार दुनिया के थानेदार अमेरिका के सामने एक नई सामरिक-आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई, लेकिन पारस्परिक होड़ का स्वरूप कुछ कुछ बदल गया। कुलमिलाकर चीन अब अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। इससे अमेरिका भारत की ओर मुड़ा, लेकिन भारतीय नेतृत्व की सतर्कता की वजह से 2025 आते आते अपने कुटिल इरादों में नाकामयाब हो गया।

बताते चलें कि नया कोल्ड वार पुराने भू-सामरिक तनाव का ही एक परिवर्तित भू-राजनीतिक तनाव है, जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है। देखने में तो यह शीत युद्ध के जैसा ही है लेकिन यह प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष के बजाय आर्थिक, तकनीकी, व्यापारिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। दोनों के बीच एशिया खासकर अरब और भारतीय उपमहाद्वीप पर वर्चस्व स्थापित करने को लेकर होड़ मची हुई है। यूरोप से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक इसकी आंच पहुंच चुकी है।

मसलन, यह नया शीत युद्ध 2010 के दशक के अंत से प्रचलित हुआ, जब अमेरिका ने चीन की बढ़ती आर्थिक शक्ति, दक्षिण चीन सागर में विस्तारवाद, तकनीकी चोरी और मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई। तब व्यापार युद्ध, हुआवेई (Huawei) प्रतिबंध और टिकटॉक जैसे मुद्दे इसके उदाहरण हैं। जहां तक इस नया शीत युद्ध के मुख्य पक्ष की बात है तो इसमें अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो वाले यूरोपीय देश, दक्षिण कोरिया, क्वाड (QUAD) (अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया) और ऑकुस (AUKUS) जैसे गठबंधन के माध्यम से चीन का मुकाबला करने की रणनीति अख्तियार किये हुए हैं, लेकिन रूसी मित्रता की वजह से भारत अक्सर गुटनिरपेक्षता की आड़ लेकर तटस्थ हो जाता है।

वहीं, चीन और उसके सहयोगी देश-रूस, उत्तर कोरिया, ईरान, पाकिस्तान (दोहरी चाल चलते हुए) और कुछ अफ्रीकी देशों यथा ब्राजील के साथ ब्रिक्स (BRICS), जिसमें भारत भी शामिल है, को विस्तार देते हुए जवाबी पलटवार करते जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत-पाकिस्तान अपने अपने पुराने कैम्प के साथ प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, जिससे चीनी पक्ष का पलड़ा भारी हुआ है।

देखा जाए तो दोनों पक्षों के बीच व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा (जैसे-चिप्स और एआई), ताइवान मुद्दा, दक्षिण चीन सागर में विस्तारवाद और अफ्रीका-प्रशांत में प्रभाव के लिए पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। अमेरिकी नादानी से 2025 तक यह मल्टी-पोलर हो गया है, जहां भारत जैसे देश तटस्थ भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, ताइवान और ईरान जैसे देश क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार यह द्विध्रुवीय से बहुध्रुवीय संघर्ष बन गया है।

इस प्रकार नया कोल्ड वार मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच माना जाता है, जिसमें रूस एक प्रमुख चीनी सहयोगी के रूप में उभर रहा है। जबकि नाटो देश अमेरिका के स्वाभाविक सहयोगी रहे हैं। ये देश अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया से लेकर मध्य-पश्चिम एशिया तक आर्थिक, तकनीकी और सैन्य प्रभाव के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जबकि भारत जैसे मजबूत कई अन्य देश तटस्थ या संतुलित भूमिका निभा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विश्लेषक भी बताते हैं कि नया कोल्ड वार में भारत तटस्थ और संतुलित भूमिका निभा रहा है, न तो पूरी तरह अमेरिका के साथ है और न ही चीन के साथ। सरल शब्दों में कहें तो जहां एक तरफ भारत QUAD और I2U2 जैसे गठबंधनों के माध्यम से अमेरिकी पक्ष को मजबूत करता है, वहीं दूसरी ओर रूस से तेल खरीदकर और BRICS में सक्रिय रहकर संतुलन बनाए रखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ओर भारत जहां प्रमुख गठबंधन QUAD सदस्य देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद-प्रशांत में चीन के विस्तारवाद का मुकाबला कर रहा है। वहीं दूसरी ओर BRICS और SCO मंच पर चीन-रूस के साथ आर्थिक सहयोग, वैश्विक दक्षिण की आवाज बुलंद कर रहा है।

दरअसल, ऐसा करके भारत अपनी "रणनीतिक स्वायत्तता" की नीति अपनाता है, जहां यह दोनों पक्षों से लाभ लेता है। साथ ही वह ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर में शांति का समर्थन तो करता है, लेकिन सीधे टकराव से दूर रहता है। वैश्विक मंचों पर भारत विकासशील देशों का नेतृत्व कर रहा है। इस प्रकार भारत की भूमिका का सबसे बड़ा भू-राजनीतिक लक्ष्य रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना है। यह बहुध्रुवीय विश्व में संतुलनकारी भूमिका निभाकर आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना चाहता है।

देखा जाए तो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के माध्यम से भारत, अमेरिका-चीन-रूस जैसे गुटों से बंधा नहीं रहना चाहता है, बल्कि वह क्वाड (QUAD), ब्रिक्स (BRICS) और एससीओ (SCO) जैसे मंचों पर सक्रिय रहकर वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करता है। इसका क्षेत्रीय प्रभाव यह होता है कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवाद का मुकाबला करते हुए IMEC कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स से व्यापारिक पहुंच बढ़ाना चाहता है। साथ ही पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश) के साथ संतुलन बनाए रखता है।

इसके पीछे भारत की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा यह है कि वह 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किये हुए है, जहां सैन्य आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत), जलवायु नेतृत्व (ISA) और डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रमुखता पूर्वक जोर दिया जा रहा हैं।

अभियान

पाने की चाह और पास की दौलत के बीच जीवन का असली सच

वो सब कुछ कीमती है जो तुम पाना चाहते हो, मगर वो सब अनमोल है जो तुम्हारे पास है—यह पंक्ति केवल एक सुंदर विचार नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा आईना है, जिसमें हर इंसान को खुद को देखकर ठहर जाना चाहिए। मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा आगे देखने की रही है। वह भविष्य के सपनों में जीता है, आने वाले कल की योजनाएं बनाता है और उन चीज़ों के पीछे दौड़ता है, जिन्हें वह अभी तक हासिल नहीं कर पाया। बेहतर जीवन, ज्यादा पैसा, बड़ा पद, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक सुविधाएं—इच्छाओं की यह सूची कभी समाप्त नहीं होती। इन्हीं इच्छाओं के पीछे भागते हुए इंसान अक्सर उस सच को भूल जाता है, जो उसके हाथों में पहले से मौजूद होता है।

जो हम पाना चाहते हैं, वह हमें आकर्षित करता है क्योंकि वह अभी दूर है। दूरी चीज़ों को चमकदार बना देती है। हमें लगता है कि जिस दिन वह लक्ष्य मिल जाएगा, उसी दिन जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अनुभव बताता है कि एक लक्ष्य पूरा होते ही दूसरा लक्ष्य जन्म ले लेता है। एक चाह पूरी होती है और मन तुरंत अगली चाह की ओर भागने लगता है। इस निरंतर दौड़ में जो सबसे ज्यादा अनदेखा होता है, वह है वर्तमान—वह समय, वह संबंध, वह सुकून, जो इसी पल हमारे पास है।

आज का इंसान भविष्य की चिंता में इतना डूबा हुआ है कि वह वर्तमान को जीना ही भूल गया है। वह सोचता है कि जब यह मिल जाएगा, तब खुश रहूंगा; जब वहां पहुंच जाऊंगा, तब चैन मिलेगा। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि "तब" कभी आता ही नहीं। खुशी हमेशा आगे खिसकती रहती है, और वर्तमान हाथ से फिसलता चला जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि जीवन कोई मंज़िल नहीं, बल्कि हर दिन चलने वाली एक यात्रा है, जिसे जीते हुए ही उसका आनंद लिया जा सकता है।

जो कुछ हमारे पास है, वह हमें अक्सर साधारण लगता है। रोज़ दिखने वाला चेहरा, रोज़ मिलने वाला साथ, रोज़ की दिनचर्या—सब कुछ सामान्य सा लगने लगता है। लेकिन यही सामान्यता दरअसल जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। स्वस्थ शरीर से उठकर सुबह देख पाना, अपनों की आवाज़ सुन पाना, दो वक्त का भोजन, सिर पर छत और मन में थोड़ी सी शांति—ये सब किसी खजाने से कम नहीं हैं। फिर भी हम इन्हें तब तक अनमोल नहीं मानते, जब तक इनमें से कोई एक चीज़ हमसे छिन न जाए।

आज तुलना ने इंसान को भीतर से बेचैन कर दिया है। सोशल मीडिया की दुनिया ने दूसरों की उपलब्धियों को हमारे सामने इस तरह परोस दिया है कि हमें अपना जीवन फीका लगने लगता है। कोई कहीं घूम रहा है, कोई बड़ी गाड़ी में बैठा है, कोई ऊंचे पद पर पहुंच गया है—इन सबको देखकर हम अपने जीवन को अधूरा समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो हमें दिख रहा है, वह किसी के जीवन का केवल एक हिस्सा है, पूरी सच्चाई नहीं। तुलना की यह आदत हमारे मन से संतोष छीन लेती है और जो हमारे पास है, उसकी कद्र कम कर देती है।

जीवन की सबसे अनमोल चीज़ें वही होती हैं, जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। माता-पिता का आशीर्वाद, जीवनसाथी का भरोसा, बच्चों की मासूम हंसी, दोस्तों का साथ, स्वास्थ्य की सहजता और मन की शांति—इनका कोई मूल्य टैग नहीं होता, लेकिन इनके बिना जीवन खोखला हो जाता है। जब ये सब हमारे पास होते हैं, तब हम इन्हें स्वाभाविक मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई एक भी कम होने लगता है, तब अहसास होता है कि यही तो असली दौलत थी।

स्वास्थ्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब शरीर ठीक होता है, तब हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। देर रात तक जागना, अनियमित खानपान, तनाव—सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जब शरीर जवाब देने लगता है, तब समझ आता है कि स्वस्थ रहना कितना बड़ा वरदान था। उसी तरह रिश्ते भी हैं। हम सोचते हैं कि अपनों के लिए समय बाद में निकाल लेंगे, अभी तो काम ज़रूरी है। लेकिन समय निकल जाता है और बाद में केवल पछतावा रह जाता है। जीवन में आगे बढ़ना गलत नहीं है। सपने देखना, लक्ष्य बनाना और मेहनत करना ज़रूरी है। लेकिन समस्या तब होती है, जब पाने की चाह इतनी प्रबल हो जाती है कि पास की चीज़ें महत्वहीन लगने लगती हैं। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। प्रयास भी जरूरी है और संतोष भी। जो व्यक्ति केवल संतोष में डूबा रहता है, वह ठहर जाता है, और जो केवल चाह में जीता है, वह कभी चैन नहीं पाता। इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर ही जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है।

कृतज्ञता वह भाव है, जो इंसान को भीतर से समृद्ध बनाता है। जब हम रोज़ यह सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, तब मन में खालीपन भरता है। लेकिन जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या है, तब वही मन भरने लगता है। एक साधारण सा दिन, एक शांत शाम, किसी अपने की एक मुस्कान—ये छोटी-छोटी बातें जीवन को बड़ा बना देती हैं। कृतज्ञ इंसान के लिए साधारण क्षण भी उत्सव बन जाते हैं।

समय जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। पैसा फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे, बाद में मिलेंगे, बाद में जिएंगे। लेकिन जीवन "बाद में" के लिए नहीं बना। जो आज है, वही सच है। बच्चों का बचपन, माता-पिता की उपस्थिति, रिश्तों की गर्माहट—सब कुछ समय के साथ बदलता चला जाता है। इन्हें टालना नहीं, बल्कि जीना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन पाने और पास के बीच की समझ का नाम है। जो तुम पाना चाहते हो, उसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करो, लेकिन जो तुम्हारे पास है, उसे कभी हल्का मत समझो। क्योंकि अक्सर वही चीज़ें, जो हमें सामान्य लगती हैं, कल हमारी सबसे बड़ी याद बन जाती हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि कीमती और अनमोल में क्या अंतर है, तब जीवन की दौड़ थकान नहीं देती, बल्कि संतोष और शांति से भर देती है। यही समझ जीवन को वास्तव में सार्थक बनाती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

गुजरात भिंडी उत्पादन में देशभर में अग्रसर

वर्ष 2024-25 में कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में 14,000 हेक्टेयर में लगभग 1.5 लाख टन भिंडी का उत्पादन हुआ

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ एवं सौराष्ट्र 2026 से पूर्व बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति

(जीएनएस)। गांधीनगर, 29 दिसंबर : प्रगतिशील नीतियों, आधुनिक कृषि पद्धतियों तथा किसानों की सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप गुजरात का बागवानी क्षेत्र राज्य के कृषि विकास का शक्तिशाली इंजन बना है। यह सकारात्मक प्रगति राजकोट में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ एवं सौराष्ट्र 2026 से पूर्व राज्य के लिए उत्साहजनक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है, जहाँ कच्छ एवं सौराष्ट्र की कृषि एवं बागवानी उपलब्धियों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से मजबूत आधार

गुजरात का बागवानी विभाग एमआईडीएच/एनएचएम (एकीकृत बागवानी विकास के लिए मिशन/राष्ट्रीय बागवानी मिशन) जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के साथ अनेक राज्य स्तरीय प्रोत्साहक योजनाएँ सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। इन योजनाओं के तहत क्षेत्र आधारित क्लस्टर विकास, संरक्षित खेती, कटाई के बाद की ढाँचागत सुविधाएँ, कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ प्लांट सामग्री पहल तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। एमआईडीएच अंतर्गत किसानों तथा एफपीओ को हाईटेक बागवानी, पॉलीहाउस, पैकहाउस, ग्रैडिंग-पैकिंग लाइन, प्रशिक्षण, बाजार कनेक्टिविटी तथा प्रदर्शनियों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

भिंडी बुवाई तथा उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर

गुजरात सरकार के बागवानी निदेशक के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान भिंडी के बुवाई क्षेत्रफल तथा कुल उत्पादन में गुजरात ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य में लगभग 93,955 हेक्टेयर क्षेत्र में भिंडी की बुवाई हुई थी, जिसके फलस्वरूप 11.68 लाख टन उत्पादन दर्ज हुआ था। इस कुल आँकड़े में कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कच्छ-सौराष्ट्र का राज्य के कुल भिंडी बुवाई क्षेत्र का लगभग 15 प्रतिशत तथा कुल उत्पादन का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2024-25 के दौरान कच्छ-सौराष्ट्र के 12 जिलों में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भिंडी की बुवाई हुई, जिससे लगभग 1.5 लाख टन उत्पादन प्राप्त हुआ है।

सब्जी उत्पादन में राज्य का उल्लेखनीय योगदान

वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के कुल सब्जी उत्पादन में गुजरात का योगदान 7.66 प्रतिशत रहा। उसी अवधि में कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र ने 2,32,584 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती कर 47,91,504 मैट्रिक टन सब्जी उत्पादन हासिल किया है। प्रति हेक्टेयर 20.60 मैट्रिक टन उत्पादकता किसानों की बढ़ती कार्यक्षमता, सुधारी गईं कृषि पद्धतियों तथा मजबूत कृषि ढाँचे की प्रतिबिंब है।

बागवानी फसलें : कृषि विकास का आधारस्तंभ

उच्च उत्पादकता तथा अधिक आय के कारण बागवानी फसलें राज्य के कृषि विकास में अभिन्न अंग बन गई हैं। राज्य सरकार के सक्रिय कदमों तथा किसान अनुकूल नीतियों के फलस्वरूप आज बागवानी फसलें गुजरात के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र में लगाई जाती हैं, जो उनके बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

वीजीआरसी 2026 : कच्छ एवं सौराष्ट्र की उपलब्धियों का मंच

यह मजबूत प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, जब गुजरात जनवरी-2026 के दूसरे सप्ताह में राजकोट में कच्छ एवं सौराष्ट्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ एवं सौराष्ट्र का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस के साथ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जीबिशन (वीजीआरई) जनवरी-2026 के दौरान उसी स्थान पर आयोजित होगा। वीजीआरसी राज्य सरकार की संतुलित क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करेगी, जबकि कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियाँ दर्शाने तथा निवेश के लिए नए मार्ग खोलने का एक समर्पित प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। वीजीआरसी 2026 भारत तथा विदेश के नीति निर्माताओं, उद्योग नेताओं, वैश्विक विशेषज्ञों, नवीनताओं तथा हिस्सेदारों को एक साथ लाएगी। केन्द्रित क्षेत्रीय सत्रों, प्रदर्शनियों तथा सहयोगी मंचों द्वारा वीजीआरसी इस बात पर प्रकाश डालेगी कि कच्छ एवं सौराष्ट्र कृषि प्रगति तथा टिकाऊ विकास के आगामी चरण का नेतृत्व करने के लिए किस प्रकार सज्ज है।

भावनगर मंडल से होकर चलने वाली भावनगर बान्द्रा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

टिकटों की बुकिंग 30 दिसंबर (मंगलवार) से शुरू होगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनस स्टेशन से प्रत्येक गुरूवार को चलने वाली भावनगर-बान्द्रा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 09207 बांद्रा टर्मिनस-भावनगर स्पेशल, जिसे पहले 26 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 27 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह ट्रेन बान्द्रा टर्मिनस स्टेशन से प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 09.30 बजे प्रस्थान करती है और उसी दिन रात्रि 23.45 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचती है।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09208 भावनगर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल, जिसे पहले 25 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 26 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह ट्रेन भावनगर टर्मिनस स्टेशन से प्रत्येक गुरूवार को दोपहर 14.50 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन प्रातः 06.00 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचती है।

ट्रेन संख्या 09208/09207 की बुकिंग 30 दिसंबर, 2025 (मंगलवार) से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। इस ट्रेन के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए, विशेष किराये पर चल रही 09 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09085/09086 मुंबई सेंट्रल – इंदौर स्पेशल (त्रि-साप्ताहिक)
ट्रेन संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल – इंदौर स्पेशल को 30 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09086 इंदौर – मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 31 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
2. ट्रेन संख्या 09083/09084 मुंबई सेंट्रल – भगत की कोठी स्पेशल (त्रि-साप्ताहिक)
ट्रेन संख्या 09083 मुंबई सेंट्रल – भगत की कोठी स्पेशल को 25 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09084 भगत की कोठी – मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 27 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
3. ट्रेन संख्या 09001/09002 मुंबई सेंट्रल – भिवानी स्पेशल (त्रि-साप्ताहिक)
ट्रेन संख्या 09001 मुंबई सेंट्रल – भिवानी स्पेशल को 27 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09002 भिवानी – मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
4. ट्रेन संख्या 09207/09208 बांद्रा टर्मिनस – भावनगर टर्मिनस स्पेशल (साप्ताहिक)
ट्रेन संख्या 09207 बांद्रा टर्मिनस – भावनगर टर्मिनस स्पेशल को 27 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09208 भावनगर टर्मिनस – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को भी 27 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
5. ट्रेन संख्या 09415/09416 बांद्रा टर्मिनस – गांधीधाम स्पेशल (साप्ताहिक)
ट्रेन संख्या 09415 बांद्रा टर्मिनस – गांधीधाम स्पेशल को 26 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09416 गांधीधाम – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 26 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
6. ट्रेन संख्या 09055/09056 बांद्रा टर्मिनस – उधना स्पेशल
ट्रेन संख्या 09055 बांद्रा टर्मिनस – उधना स्पेशल को 26 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09056 उधना – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 25 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
7. ट्रेन संख्या 09211/09212 गांधीग्राम – बोटाद स्पेशल (अनारक्षित)
ट्रेन संख्या 09211 गांधीग्राम – बोटाद स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09212 बोटाद – गांधीग्राम स्पेशल को भी 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
8. ट्रेन संख्या 09215/09216 गांधीग्राम – भावनगर टर्मिनस स्पेशल (अनारक्षित)
ट्रेन संख्या 09215 गांधीग्राम – भावनगर टर्मिनस स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09216 भावनगर टर्मिनस – गांधीग्राम स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
9. ट्रेन संख्या 09529/09530 धोला – भावनगर टर्मिनस स्पेशल (अनारक्षित)
ट्रेन संख्या 09529 धोला जं.– भावनगर टर्मिनस स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09530 भावनगर टर्मिनस – धोला जं. स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09085, 09083, 09001, 09086, 09207, 09208, 09415, 09416, 09055 एवं 09056 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 30 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सोना वायदा 1815 रुपये और चांदी वायदा 4587 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा में 64 रुपये की बढ़त

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 709906.7 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 111464.58 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 598426.77 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 35291 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4514.68 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 89786.39 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 139808 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 140444 रुपये और नीचे में 137646 रुपये पर पहुंचकर, 139873 रुपये के पिछले बंद के सामने 1815 रुपये या 1.3 फीसदी घटकर 138058 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 214 रुपये या 0.19 फीसदी गिरकर 110891 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 134 रुपये या 0.96 फीसदी गिरकर 13841 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी जनवरी वायदा 137628 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 138269 रुपये और नीचे में 135777 रुपये पर पहुंचकर, 1723 रुपये या 1.25 फीसदी गिरकर 136066 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम 137602 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 138983 रुपये और नीचे में 135100 रुपये पर पहुंचकर, 137605 रुपये के पिछले बंद के सामने 1339 रुपये या 0.97 फीसदी गिरकर 136266 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 247194 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 254174 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 232663 रुपये पर पहुंचकर, 239787 रुपये के पिछले बंद के सामने 4587 रुपये या 1.91 फीसदी घटकर 235200 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 3555 रुपये या 1.48 फीसदी गिरकर 236807 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 3563 रुपये या 1.48 फीसदी लुढ़ककर 236865 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कमोडिटी वायदाओं में 111464.58 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 598426.77 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 89786.39 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 35291 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 18787.12 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 21.7 रुपये या 1.72 फीसदी लुढ़ककर 1237.6 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 8.55 रुपये या 2.74 फीसदी गिरकर 303.1 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 5.7 रुपये या 1.91 फीसदी लुढ़ककर 293.35 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 5 पैसे या 0.03 फीसदी टूटकर 183.05 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2962.92 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5182 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5253 रुपये और नीचे में 5170 रुपये पर पहुंचकर, 64 रुपये या 1.24 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 5246 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 59 रुपये या 1.14 फीसदी की बढ़त के साथ 5243 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 354 रुपये के भाव पर खूलकर, 356.6 रुपये के दिन के उच्च और 342.7 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 352.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 4.1 रुपये या 1.16 फीसदी गिरकर 348.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 3.9 रुपये या 1.11 फीसदी औंधकर 348.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 978 रुपये के भाव पर खूलकर, 80 पैसे या 0.08 फीसदी की नरमी के साथ 973.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 29682.58 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 60103.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 16317.90 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 1173.15 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 65.20 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 1230.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 519.35 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2430.99 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 17347 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 77127 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 23775 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 361352 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 38549 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 16915 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40649 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 106696 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20308 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 34309 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 36380 पॉइंट पर खूलकर, 36815 के उच्च और 35182 के नीचले स्तर को छूकर, 453 पॉइंट घटकर 35291 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 29.8 रुपये की बढ़त के साथ 167.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.15 रुपये की गिरावट के साथ 29.15 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 844.5 रुपये की गिरावट के साथ 468 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 249000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1918 रुपये की बढ़त के साथ 11736 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 17.45 रुपये की बढ़त के साथ 59.52 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.93 रुपये की गिरावट के साथ 14 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 35.6 रुपये की गिरावट के साथ 126.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.05 रुपये की बढ़त के साथ 30.05 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 138000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 577.5 रुपये की बढ़त के साथ 1192 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 801 रुपये की बढ़त के साथ 3652.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 15.76 रुपये की बढ़त के साथ 40.34 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 5.91 रुपये की बढ़त के साथ 12 रुपये हुआ।

भावनगर मंडल के स्टेशन अधीक्षक श्री दीपक कुमार गुप्ता दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति पदक (विशिष्ट सेवा) एवं केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में वर्तमान में स्टेशन अधीक्षक (भावनगर टर्मिनस) के पद पर कार्यरत श्री दीपक कुमार गुप्ता को उनकी उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्यनिष्ठा एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए देश के दो अत्यंत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनसेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक (विशिष्ट सेवा) तथा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक (जांच में उत्कृष्टता) प्रदान किया गया। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी दी कि ये पुरस्कार 26 एवं 27 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित गरिमामय अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किए गए। पदक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा, माननीय गृह राज्य मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों के गणमान्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रदान किए गए। इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने श्री गुप्ता को बधाई दी एवं उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में अपने कार्यकाल के दौरान श्री दीपक कुमार गुप्ता ने अनेक संवेदनशील एवं राष्ट्रीय महत्व के उच्च-प्रोफ़ाइल मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें पुलवामा आतंकी हमला, जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले, क्रॉस-बॉर्डर एलओसी ट्रेड, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आतंकी वित्तपोषण, आईएसआईएस से जुड़े विभिन्न मॉड्यूल, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) मामला, एक उच्च-प्रोफ़ाइल हत्या प्रकरण तथा मुंबई ब्लास्ट मामला शामिल हैं। इन मामलों में उनके असाधारण योगदान एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक (विशिष्ट सेवा) से सम्मानित किया गया।

एनआईए के एक प्रमुख प्रकरण में देशभर के उच्च शिक्षित युवाओं द्वारा एक ही दिन में अनेक सिलसिलेवार विस्फोटों की साजिश रची गई थी, जिसमें आतंकी फंडिंग कई देशों से क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से की जा रही थी। इस मामले में छह आतंकवादियों की गिरफ्तारी, सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किए जाने तथा पाँच आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराए जाने में श्री गुप्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। साइबर, वित्तीय एवं क्रिप्टोकरेंसी जांच में उनकी उत्कृष्ट दक्षता एवं उच्च दबाव की परिस्थितियों में निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक (जांच में उत्कृष्टता) प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी में अपनी सेवाओं के दौरान श्री गुप्ता को केंद्रीय गृह मंत्री स्पेशल ऑपरेशन पदक, महानिदेशक, एनआईए की प्रशस्ति सूची, तथा अनेक प्रमाण-पत्र, प्रशंसा पत्र एवं नकद पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। भारतीय रेल में अपने पूर्व कार्यकाल के दौरान भी उन्हें विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कई बार सम्मानित किया गया है, जिनमें डीआरएम स्तर पर तीन, एसडीजीएम स्तर पर एक तथा जीएम स्तर पर दो पुरस्कार शामिल हैं।

वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री सी. आर. गरूडा ने बताया कि श्री दीपक कुमार गुप्ता का व्यावसायिक आचरण ईमानदारी, साहस एवं राष्ट्र के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक है। वर्तमान में भारतीय रेल में सेवाएँ प्रदान करते हुए भी वे अनुशासन, उत्तरदायित्व एवं जनसेवा के मूल्यों को निरंतर बनाए हुए हैं। इन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से उनका सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों की पहचान है, बल्कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए समर्पण एवं उत्कृष्टता के साथ राष्ट्रसेवा करने की प्रेरणा भी है।

नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी का खतरनाक खेल पुलिस की सख्ती के बाद थम आठ युवक गिरफ्तार, दो वाहन जब्त – सड़क सुरक्षा को लेकर उठाया बड़ा कदम

(जीएनएस)। फिरोजाबाद। नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी और तेज रफ्तार में खतरनाक करतब करने वाले युवकों के खिलाफ फिरोजाबाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया और इस दौरान स्टंट में इस्तेमाल दो वाहनों को सीज कर लिया। यह कार्रवाई सड़क पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने और हाईवे पर हो रहे जानलेवा हादसों को रोकने के लिए की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर जिले में लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना टूंडला पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी।

सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर कुछ युवक हुंडई क्रेटा और महिंद्रा एक्सयूवी-700 से स्टंट कर रहे हैं और सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों व राहगीरों के लिए खतरा बन रहे हैं। तुरंत गश्त पर निकली पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपितों को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार, ये युवक तेज रफ्तार में वाहन चलाकर सड़कों पर खतरनाक करतब कर रहे थे, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। इनकी इस हरकत से न केवल हाईवे पर यातायात बाधित हो रहा था, बल्कि आम जनता की जान पर भी संकट मंडरा रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान विनायक उर्फ ईशू, मनोज उर्फ हैडन, मोहित, पंकज, अभिषेक, आशीष, निखिल और यशू के रूप में हुई है। सभी आरोपित जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों के साथ स्टंट में प्रयुक्त दो वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के जोखिम को रोका जा सके।

सौरभ दीक्षित ने इस कार्रवाई को हाईवे पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि सड़क पर स्टंटबाजी और तेज रफ्तार में खतरनाक ड्राइविंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे भी ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते खतरे को टाला जा सके। पुलिस ने यह साफ किया कि हाईवे पर होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए नियमित गश्त जारी रहेगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

पश्चिम रेल्वे द्वारा विविध स्पेशल ट्रेनों की ट्रिप चलाइ जाएगी ।

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तिथियाँ	से विस्तृत
09085	मुंबई सेंट्रल - इंदौर	सोम, बुध और शुक्र	30.01.2026
09086	इंदौर - मुंबई सेंट्रल	मंगल, गुरु और शनि	31.01.2026
09207	बांद्रा टर्मिनस - भावनगर टर्मिनस	शुक्रवार	27.02.2026
09208	भावनगर टर्मिनस - बांद्रा टर्मिनस	गुरुवार	27.02.2026
09415	बांद्रा टर्मिनस - गांधीधाम	गुरुवार	26.02.2026
09416	गांधीधाम - बांद्रा टर्मिनस	गुरुवार	26.02.2026

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

उपर दी गई ट्रेनों के बढ़ाए गए ट्रिप के लिए बुकिंग 30.12.2025 से सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। ये ट्रेनें स्पेशल किराए पर स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाइ जाएगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly
हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly
हमें फॉलो करें: Instagram/WesternRly

कृपया सभी आरक्षीत टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें ।

फ्रॉड की गिनती घटी, मगर रकम ने उड़ाए होश: डिजिटल स्कैम से लेकर कर्ज धोखाधड़ी तक बैंकिंग सिस्टम पर बढ़ता दबाव

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के बैंकिंग सेक्टर में एक अजीब और चिंताजनक विरोधाभास सामने आया है। चालू वित्त वर्ष में बैंकिंग फ्रॉड के मामलों की संख्या में तो भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इन धोखाधड़ियों में शामिल रकम में तेज उछाल ने नियामकों और बैंकों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25' में यह खुलासा हुआ है कि अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच फ्रॉड के मामले घटकर महज 5,092 रह गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 18,386 थी। इसके बावजूद फ्रॉड से जुड़ी कुल राशि 16,659 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,367 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो यह संकेत देती है कि अब कम लेकिन बड़े और ज्यादा संगठित घोटाले सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर कुल 23,879 फ्रॉड मामले दर्ज किए गए, जिनमें शामिल राशि 34,771 करोड़ रुपये रही। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि रकम में आई इस बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च 2023 के आदेश के अनुपालन में पुराने मामलों की दोबारा रिपोर्टिंग भी है। इसके बावजूद यह तथ्य अपनी जगह कायम है कि बैंकिंग सिस्टम में धोखाधड़ी का स्वरूप बदल रहा है। अब छोटे-छोटे मामलों की बजाय ऐसे फ्रॉड सामने आ रहे हैं जिनमें रकम कहीं ज्यादा है और असर कहीं गहरा।

अगर पिछले वित्त वर्ष से तुलना की जाए तो फ्रॉड की कुल राशि में तीन गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। खास तौर पर कर्ज यानी एडवांस से जुड़े फ्रॉड इसमें सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरे हैं। इनसे जुड़ी रकम 31,911 करोड़ रुपये तक पहुंच गई

है, जो कुल फ्रॉड राशि का बड़ा हिस्सा है। आरबीआई ने रिपोर्ट में माना है कि बैंकिंग फ्रॉड न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि बैंकों की साख, परिचालन क्षमता और सबसे अहम—ग्राहकों के भरोसे को भी कमजोर करते हैं। फ्रॉड की प्रकृति पर नजर डालें तो संख्या के लिहाज से कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े मामलों का दबदबा अब भी कायम है। कुल मामलों में इनकी हिस्सेदारी 66.8 प्रतिशत रही, हालांकि राशि के लिहाज से इनका योगदान कम है। इसके उलट, कर्ज से जुड़े फ्रॉड संख्या में कम होने के बावजूद रकम के मामले में भारी पड़ रहे हैं और कुल फ्रॉड राशि का 33.1 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं से जुड़ा है। निजी बैंकों में फ्रॉड के मामलों की संख्या ज्यादा दर्ज की गई है, जहां कुल मामलों का 59.3 प्रतिशत रिपोर्ट हुआ, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फ्रॉड से जुड़ी कुल राशि का 70.7 प्रतिशत हिस्सा पाया गया। इसका साफ मतलब है कि निजी बैंकों में डिजिटल और कार्ड फ्रॉड ज्यादा हैं, जबकि सरकारी बैंकों में बड़े कर्ज घोटाले प्रमुख चुनौती बने हुए हैं।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बीते वर्ष की तुलना में कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड की हिस्सेदारी सभी तरह के बैंकों में कुछ हद तक घटी है। इसे साइबर सुरक्षा उपायों और जागरूकता अभियानों का असर माना जा रहा है, लेकिन पूरी तरह राहत की स्थिति अभी दूर है। डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दायरे के साथ स्कैम के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं, जिनसे निपटना बैंकों और नियामकों के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए आरबीआई ने तकनीक के सहारे बड़ा कदम उठाया है। खास तौर पर म्यूल अकाउंट्स पर लगाम लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली 'म्यूलहंटर डॉट एआई' को लागू किया गया है। म्यूल अकाउंट वे खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल अपराधी दूसरे लोगों के पुराने या निष्क्रिय खातों के जरिए अवैध लेनदेन के लिए करते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा विकसित यह तकनीक ऐसे खातों की तेजी से पहचान करने में सक्षम है। 17 दिसंबर 2025 को इसे एक साथ 23 बैंकों में लागू किया गया, जिससे उम्मीद की जा रही है कि फ्रॉड को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकेगा। इन तमाम चिंताओं के बीच आरबीआई की रिपोर्ट बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की तस्वीर भी पेश करती है। मार्च 2025 के अंत तक भारतीय बैंकिंग सिस्टम का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी ग्रॉस एनपीए अनुपात घटकर 2.2 प्रतिशत पर आ गया है, जो पिछले कई दशकों का सबसे निचला स्तर है। शुद्ध एनपीए भी घटकर 0.5 प्रतिशत रह गया है। इसका मतलब यह है कि बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है और जोखिम प्रबंधन पहले से बेहतर हुआ है।

मुनाफे के मोर्चे पर भी बैंकों की स्थिति मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में सभी वाणिज्यिक बैंकों का संयुक्त शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 14.8 प्रतिशत बढ़कर 4.01 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, हालांकि इसकी रफ्तार पिछले वर्षों की तुलना में कुछ धीमी रही। इसके बावजूद यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर आर्थिक झटकों को झेलने की क्षमता रखता है और अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार बना हुआ है।

आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया है कि एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम अर्थव्यवस्था के बुनियादी जोखिमों से बचाने में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। हालांकि फ्रॉड की बढ़ती रकम यह साफ संकेत देती है कि आने वाले समय में बैंकों को सिर्फ मुनाफे और कर्ज विस्तार पर नहीं, बल्कि जोखिम नियंत्रण, तकनीकी निगरानी और ग्राहक सुरक्षा पर भी बराबर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर फ्रॉड की रकम पर समय रहते लगाम नहीं लगी, तो यह मजबूती के दावों पर भारी पड़ सकती है।

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने थाम दी उड़ानों की रफ्तार, इंडिगो की 80 फ्लाइट रद्द होने से देशभर में हजारों यात्री प्रभावित

(जीएनएस)। नई दिल्ली। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में जारी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने सामान्य जनजीवन के साथ-साथ हवाई यातायात को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। सोमवार को देश की प्रमुख घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो को खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण अपने नेटवर्क की 80 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इसका सीधा असर राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित मुंबई, बेंगलुरु, कोचीन, हैदराबाद, कोलकाता, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, देहरादून, इंदौर, पटना और भोपाल जैसे बड़े हवाई अड्डों पर देखने को मिला, जहां यात्रियों को लंबा इंतजार, उड़ान रद्द होने की सूचना और यात्रा योजनाओं में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ा।

दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कई बार बेहद खतरनाक स्तर तक गिर गई। हवाई अड्डों पर रनवे ऑपरेशन प्रभावित हुआ और पायलटों को लैंडिंग और टेक-ऑफ के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। मौसम की इसी चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए इंडिगो ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया। एयरलाइन का कहना है कि कम दृश्यता में उड़ानों का संचालन यात्रियों और क्रू दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए मौसम सामान्य होने तक उड़ानों को रद्द या विलंबित करना जरूरी हो जाता है।

इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति अवश्य जांच लें। कंपनी ने यात्रियों को अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए रीयल-टाइम अपडेट लेने की सलाह दी है। एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली और उत्तर भारत के कई हवाई अड्डों पर कोहरे की स्थिति पूरी तरह नहीं सुधरी है और दोपहर तक भी उड़ानों पर इसका असर बना रह सकता है। ऐसे में यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा योजनाएं तैयार रखने और अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है।

हवाई अड्डों पर स्थिति यह रही कि कई यात्रियों को घंटों टर्मिनल में इंतजार करना पड़ा। कुछ यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई, तो कई को होटल बुकिंग और अन्य व्यवस्थाओं में बदलाव करना पड़ा। हालांकि एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ की ओर से यात्रियों को जानकारी देने और सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, लेकिन अचानक बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से अव्यवस्था की स्थिति भी बनी रही। खासकर बुजुर्ग यात्रियों, बच्चों और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी है। सर्दियों के मौसम में कोहरे की समस्या को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट प्रबंधन को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार, CAT-III जैसी उन्नत लैंडिंग प्रणालियों के बावजूद जब दृश्यता अत्यधिक कम हो जाती है, तो उड़ानों को रद्द करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को समय पर सही जानकारी दी जाए और रिफंड या रीशेड्यूलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

कोलकाता की सड़कों से विदा होने को तैयार डेढ़ सौ साल पुरानी पहचान, ट्राम की घंटियों के साथ इतिहास भी थमने की कगार पर

(जीएनएस)। कोलकाता। शहर की तंग गलियों, चौड़ी सड़कों और ऐतिहासिक इमारतों के बीच दशकों से रेंगती हुई चलने वाली ट्रामें अब अपनी आखिरी यात्रा की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। एशिया के सबसे पुराने ट्राम नेटवर्क में शुमार कोलकाता की ट्राम सेवा को बंद करने का फैसला सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के धीरे-धीरे मिटने का संकेत है, जिसने कोलकाता को बाकी महानगरों से अलग पहचान दी। बंगाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव और आधुनिक परिवहन जरूरतों के बीच ट्राम को चलाए रखना व्यावहारिक नहीं रह गया है, इसलिए इसे पूरी तरह समाप्त कर केवल एक सीमित 'हेरिटेज रूट' को ही प्रतीकात्मक रूप से बचाया जाएगा। कोलकाता में ट्राम का इतिहास 1873 से शुरू होता है, जब पहली बार घोड़ों से खींची जाने वाली ट्राम

सड़कों पर उतरी थी। यह वह दौर था, जब शहर ब्रिटिश हुकूमत का प्रमुख केंद्र था और आधुनिकता के नए प्रयोग यहीं से शुरू होते थे। 1902 में ट्राम सेवा को बिजली से चलने वाला स्वरूप मिला और इसके बाद यह कोलकाता की जीवनरेखा बन गई। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूल-कॉलेज के छात्र, बाजार जाने वाली महिलाएं और बुजुर्ग—हर वर्ग के लिए ट्राम सबसे सस्ती, सुरक्षित और भरोसेमंद सवारी थी। अपने सुनहरे समय में इस नेटवर्क के पास 340 से अधिक ट्रामें थीं और पूरा शहर पटरियों के जाल से जुड़ा हुआ था।

समय के साथ शहर बदला, आबादी बढ़ी, सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कई गुना हो गई और ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता चला गया। ऐसे में धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रामें प्रशासन की नजर में 'बाधा' बनने लगीं। एक-एक कर रूट बंद होते गए, डिपो उजड़ते गए और ट्रामों की संख्या सिमटती चली गई। आज स्थिति यह है कि शहर में 10 से भी कम ट्रामें बची हैं, जो कभी-कभार ही सड़कों पर दिखाई देती हैं। कई पुराने डिपो या तो बेच दिए गए हैं या फिर कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। जिन पटरियों पर कभी घंटियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब बसें, कारें और बाइकें दौड़ती नजर आती हैं।

सरकार का तर्क है कि आधुनिक महानगर की जरूरतें अब बदल चुकी हैं। मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है, फ्लाईओवर और चौड़ी सड़कों पर जोर दिया जा रहा है और ऐसे में ट्राम जैसी व्यवस्था शहर की रफ्तार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही। प्रशासन यह भी मानता है कि ट्राम के रखरखाव पर होने वाला खर्च और उससे मिलने वाला सीमित लाभ आर्थिक रूप से तर्कसंगत नहीं है। इसी सोच के तहत फैसला लिया गया है कि ट्राम सेवा को समाप्त कर सिर्फ एक छोटा विरासत मार्ग बचाया जाए, ताकि इतिहास की एक झलक आने वाली पीढ़ियों को दिखाई जा सके।

लेकिन इस फैसले ने कोलकाता के लोगों के दिलों में गहरी उदासी भर दी है। कई नागरिक समूह और सामाजिक संगठन इसे सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मुद्दा नहीं, बल्कि शहर की आत्मा से जुड़ा सवाल मानते हैं। 'कलकत्ता ट्राम यूजर्स एसोसिएशन' जैसे संगठन ट्राम को बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। उनका कहना है कि ट्राम पर्यावरण के लिहाज से सबसे स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन माध्यम है। जहां एक ओर दुनिया के कई शहर प्रदूषण से लड़ने के लिए ट्राम और लाइट रेल सिस्टम को दोबारा अपना रहे हैं, वहीं कोलकाता अपनी ऐतिहासिक और पर्यावरण हितैषी व्यवस्था को खुद खत्म कर रहा है। ट्राम से जुड़ी भावनाएं सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं हैं। दशकों तक ट्राम चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। 30-35 साल तक सेवा देने वाले कई कर्मचारी बताते हैं कि ट्राम सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि गर्व की पहचान थी। पीढ़ियों ने ट्राम के साथ अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे की यादें जोड़ी हैं। कॉलेज जाते छात्रों की हंसी, ऑफिस से लौटते थके चेहरों की चुप्पी और शाम के वक्त खिड़की से बाहर झांकते बुजुर्गों की नजरें—इन सबका गवाह रही है ट्राम।

नए साल के जश्न का सबसे बड़ा आकर्षण बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 31 दिसंबर तक 8 लाख पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान

(जीएनएस)। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस बार नए साल के जश्न के लिए देश के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल हो गई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद यहां पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही देश-विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। सरदार वल्लभभाई पटेल की भव्य प्रतिमा को देखने और नए साल का स्वागत खास अंदाज में करने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक, बीते शनिवार को ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में 50 हजार से ज्यादा पर्यटकों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि रविवार को यह संख्या 70 हजार के पार पहुंच गई। महज दो दिनों में एक लाख से अधिक लोगों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिहाज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है।

पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन का अनुमान है कि 31 दिसंबर तक यहां आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 8 लाख से ज्यादा हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है। यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए अलग-अलग रूट तय किए गए हैं ताकि जाम की स्थिति न बने। पार्किंग की क्षमता भी बढ़ाई गई है, जिससे बाहर से आने वाले वाहनों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही पेयजल, साफ-सफाई और पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए विशेष टीमें लगातार काम कर रही हैं।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर और उसके आसपास के इलाके में उत्सव जैसा माहौल है। ठंड के मौसम में यहां का सुहावना वातावरण पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहा है। लोग न सिर्फ प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि आसपास के पर्यटन स्थलों का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। फूलों की घाटी, सरदार सरोवर बांध, जंगल सफारी, लाइट एंड साउंड शो, एकता मॉल और विभिन्न सांस्कृतिक व मनोरंजन कार्यक्रम सैलानियों के बीच बेहद लोकप्रिय बने हुए हैं। शाम होते ही लाइट एंड साउंड शो के दौरान पूरा परिसर रोशनी और संगीत से जीवंत हो उठता है, जो नए साल के उत्साह को और बढ़ा देता है।

न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए आसपास के होटल, रिसॉर्ट्स और टेंट सिटी के संचालकों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ठहरने की सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है और खाने-पीने के लिए खास मेन्यू तैयार किए गए हैं। कई जगहों पर लाइव म्यूजिक, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष न्यू ईयर इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को यादगार अनुभव मिल सके। होटल कारोबारियों का कहना है कि इस बार बुकिंग पहले ही लगभग फुल हो चुकी है और आखिरी दिनों में और ज्यादा भीड़ आने की संभावना है।

प्रशासन का मानना है कि बेहतरीन व्यवस्थाएं, सुरक्षित माहौल और विविध पर्यटन गतिविधियों के कारण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नए साल के स्वागत के लिए एक आदर्श स्थल बनकर उभरा है। परिवार के साथ आने वाले पर्यटकों से लेकर युवाओं और विदेशी सैलानियों तक, हर वर्ग के लोग यहां खुद को सुरक्षित और सहज महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि साल के आखिरी दिनों में यह स्थान देश के सबसे व्यस्त और चर्चित पर्यटन केंद्रों में शामिल हो गया है। आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बार फिर भारत की पर्यटन क्षमता का भव्य उदाहरण पेश करने के लिए तैयार नजर आ रहा है।

वडोदरा मंडल के बाजवा - अहमदाबाद सेक्शन पर स्वदेशी “कवच 4.0” प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा रेल परिचालन में संरक्षा को और मजबूत करते के क्रम में 29 दिसंबर,2025 को 96 किलोमीटर लंबे बाजवा - अहमदाबाद सेक्शन पर कवच 4.0 सिस्टम को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया। वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के कुशल मार्गदर्शन में वडोदरा मंडल के सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन विभाग ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

कवच से लैस पहली ट्रेन 59549/59550 संकल्प फास्ट पैसेंजर 29 दिसंबर,2025 को वडोदरा से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई, जिसके लोकोमोटिव में वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके एवं वरिष्ठ अधिकारिओं ने सफ़र किया और इस स्वदेशी “कवच” प्रणाली का अवलोकन किया। पहली ट्रेन शत प्रतिशत ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी के साथ चली और इस प्रकार बाजवा - अहमदाबाद सेक्शन पर स्वदेशी “कवच 4.0”

प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशन हुआ।

वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने इस अवसर पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में रेलवे में टेक्नोलॉजी में आत्मसात किया जा रहा है। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम है, जो सिग्नल पास एट डेंजर (SPAD) की रोकथाम के साथ - साथ ऑटोमैटिक स्पीड कंट्रोल एवं आमने-सामने और पीछे से टक्करों से सुरक्षा जैसी कार्यक्षमताएं प्रदान करती है। यह ट्रैक पर RFID टैग और ट्रैक, सिग्नल और लोकोमोटिव के बीच कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रा-हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी (UHF) का इस्तेमाल करता है, जिससे केबिन में लोको पायलटों को रियल-टाइम जानकारी मिलती है, और यह सुरक्षित और ज़्यादा कुशल यात्राओं के लिए एक सतर्क रक्षक की तरह काम करता है।

96 किलोमीटर लंबे बाजवा-अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली 'कवच' प्रणाली के अंतर्गत 17 स्टेशनों को कवर किया गया है, 23 टावर स्थापित किये गए है और 192 किलो मीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गयी है। NMS डिवीजन ऑफिस, प्रतापनगर और अहमदाबाद में इंस्टॉल किया गया है। इस सेक्शन में इस प्रणाली के कमीशन होने से संरक्षा में वृद्धि के साथ साथ उच्च गति पर भी सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित होगा।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा वर्ष 2026 के लिए पश्चिम रेलवे का वॉल कैलेंडर एवं टेबल कैलेंडर का विमोचन

राष्ट्रीय गौरव के 150 वर्षों और भारतीय रेल की शाश्वत विरासत का दृश्यात्मक सफ़र

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी नववर्ष के अवसर पर वर्ष 2026 के लिए अपने वॉल कैलेंडर एवं टेबल कैलेंडर का विमोचन कर संगठन की गौरवशाली विरासत, समकालीन उपलब्धियों तथा जन-केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता द्वारा पश्चिम रेलवे मुख्यालय, चर्चगेट में प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं वरिष्ठ रेल अधिकारियों की उपस्थिति में इन कैलेंडरों का औपचारिक विमोचन किया गया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वॉल कैलेंडर 2026 का विषय “वंदे मातरम् – राष्ट्रीय गौरव और गौरवगाथा के 150 वर्ष” है, जो भारत के इस प्रतिष्ठित देशभक्ति गीत के डेढ़ सौ वर्षों का स्मरण करते हुए पश्चिम रेलवे की परिवर्तनशील यात्रा को प्रतिबिंबित करता है। यह आकर्षक एवं दृश्यात्मक रूप से समृद्ध कैलेंडर पश्चिम रेलवे की प्रमुख उपलब्धियों और आधारभूत संरचना विकास को दर्शाता है। इसमें वंदे भारत

एक्सप्रेस जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें, आधुनिक विद्युत इंजनों, उन्नत रेलवे स्टेशनों तथा एस्केलेटर और बेहतर स्टेशन संरचना जैसी उन्नत यात्री सुविधाओं के प्रमुख दृश्य शामिल हैं। ये सभी चित्र सुरक्षित, कुशल एवं विश्वस्तरीय रेल सेवाएं प्रदान करने के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। तिरंगे के सजीव रंगों में डिज़ाइन किया गया यह कैलेंडर राष्ट्रीय गौरव के भाव से जुड़ते हुए तकनीकी नवाचार एवं यात्री-केंद्रित विकास को भी उजागर करता है।

भारतीय रेल की स्थायी विरासत को प्रतिबिंबित करते हुए और अतीत की स्मृतियों को जीवंत करते हुए, श्री विनीत अभिषेक ने बताया कि टेबल कैलेंडर 2026, जिसका विमोचन भी इसी कार्यक्रम में किया गया, “इतिहास के पन्नों से गुजरती रेलगाड़ियाँ – लोकोमोटिव्स ऑन पेडेस्टल” विषय पर आधारित है और यह भारतीय रेल की गौरवशाली विरासत को समर्पित एक भावनात्मक श्रद्धांजलि है। इस कैलेंडर में पश्चिम रेलवे द्वारा संरक्षित विंटेज भाप इंजनों के मनमोहक चित्र शामिल हैं, जो उस दूरदर्शिता, समर्पण और अथक प्रयासों को दर्शाते हैं, जिन्होंने भारतीय रेल को राष्ट्रीय प्रगति का एक मजबूत स्तंभ बनाया। आज जहां यात्री वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं, वहीं ये कालजयी भाप इंजन हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब रेलगाड़ियाँ खेतों, कस्बों और शहरों से गुजरते हुए अपनी विशिष्ट सीटी की गूंज के साथ आगे बढ़ती थीं, जो रेल यात्रा के रोमांच, दृढ़ता और शाश्वत भावना का प्रतीक हैं।

वर्ष 2026 के लिए वॉल और टेबल कैलेंडरों का यह विमोचन न केवल पश्चिम रेलवे के गौरवशाली अतीत और गतिशील वर्तमान को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि राष्ट्र और यात्रियों की सेवा में नवीन ऊर्जा, नवाचार और समर्पण के साथ आगे बढ़ने के उसके संकल्प को भी पुनः सुदृढ़ करता है।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। कांदिवली–बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे द्वारा 20/21 दिसंबर, 2025 की रात से 18 जनवरी, 2026 तक कुल 30 दिनों का ब्लॉक लिया गया है। इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 30/31 दिसंबर, 2025 की रात से 6 जनवरी, 2026 तक की अवधि के दौरान विभिन्न लाइनों पर ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान अप फास्ट लाइन पर 23:15 से 03:15 बजे तक, 5वीं लाइन पर 23:00 से 03:30 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर शटडाउन मार्जिन के दौरान ब्लॉक किया जाएगा।

उपर्युक्त ब्लॉकों के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ब्लॉक के कारण प्रभावित ट्रेनों की सूची अनुलग्नक–I एवं अनुलग्नक–II में दी गई है।

नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की तेजी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ने बढ़ाई अर्थव्यवस्था की रफ्तार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। नवंबर 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन (IIP) 6.7 प्रतिशत बढ़ गया, जो अक्टूबर में त्योहारी सीजन के कारण आई मंदी के बाद अर्थव्यवस्था की मजबूत वापसी का संकेत है। रॉयटर्स के सर्वे में अर्थशास्त्रियों ने केवल 2.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक रहा। अक्टूबर 2025 में IIP केवल 0.4 प्रतिशत बढ़ा था, क्योंकि दिवाली और लंबी छुट्टियों के कारण कारखानों में काम का दबाव कम हो गया था।

नवंबर के आंकड़े पिछले साल की 5 प्रतिशत वृद्धि से भी बेहतर हैं और यह दर्शाते हैं कि त्योहारी सीजन के बाद उत्पादन सामान्य स्तर पर लौट आया और खपत में भी तेजी देखने को मिली। इस उछाल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसमें नवंबर में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बेसिक मेटल्स, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और मोटर व्हीकल्स जैसे क्षेत्रों ने औद्योगिक विकास को गति दी। माइनिंग गतिविधियों में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बिजली उत्पादन में 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस उछाल से संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता मजबूत है और आने वाले महीनों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। निवेशकों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि से नई परियोजनाओं और उत्पादन संबंधी निवेश की संभावना बढ़ जाती है।

नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में कैपिटल गुड्स में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में 7.3 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 10.3 प्रतिशत बढ़े, बेसिक मेटल्स में 10.2 प्रतिशत की तेजी आई, प्राइमरी गुड्स में मामूली 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कंज्यूमर नॉन-ड्यूरेबल्स में 7.3 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि दिखाती है कि भारतीय उत्पादन क्षेत्र की क्षमता मजबूत है। मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक मेटल्स और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। निवेशकों को इन सेक्टरों में आने वाले महीनों में अवसर मिलने की संभावना है और इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में शीर्ष योगदान देने वाले सेक्टर निम्नलिखित रहे हैं:

1.इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स – इस सेक्टर ने 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। नई परियोजनाओं और निर्माण गतिविधियों में तेजी आई है।

2.मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर – इस सेक्टर ने 11.9 प्रतिशत की वृद्धि की, जो ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थिर मांग और उत्पादन क्षमता को दर्शाता है।

3.फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिनल और बॉटनिकल प्रोडक्ट्स – इस सेक्टर में 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो दवा और स्वास्थ्य उत्पादों की मजबूत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग को रेखांकित करता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इन सेक्टरों में उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेशकों को नए प्रोजेक्ट्स और उत्पादन इकाइयों में निवेश के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। इसके अलावा, यह वृद्धि अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाने और उपभोक्ता मांग को गति देने का संकेत भी है। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि ने संकेत दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के बावजूद तेजी से उबर रही है। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख सेक्टरों में सुधार ने उत्पादन और निवेश दोनों में सकारात्मक असर डाला है। इसके परिणामस्वरूप आने वाले महीनों में रोजगार, उपभोग और निवेश के क्षेत्र में मजबूती देखने को मिल सकती है।